LOK SABHA

Wednesday, April 8, 1964/Chaitra 19, 1886 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*].

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Allotment of Land in Delhi

\+

*944. **Shri Vishram Prasad:**
Dr. L. M. Singhvi:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the land behind Safdarjang Hospital was auctioned by lot recently at Rs. 35 per square yard under the low income housing scheme; and

(b) Government's cost per square yard of this land after taking into account the development charges?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) In November 1961, 73 plots in the Safdarjung area were allotted to persons in low income group at prices ranging from Rs. 35.20 to Rs. 38 per square yard; and

(b) Rs. 39 per square yard.

Shri Vishram Prasad: In reply to a question on 21st November, 1961 it was stated that the land was acquired at Rs. 5 per sq. yd. and also that 40 per cent was the net area available for distribution as housing plots. So that, the total acquired cost comes to Rs. 12.5 per sq. yd. The development charges came to Rs. 7 per sq. yd. The total price comes to Rs. 19.5 per sq. yd. I want to know why the Government charged Rs. 35 per sq. yd. and has made so much profit.

Shri L. N. Mishra: The cost of the land comes to Rs. 39 per sq. yd. as against the price charged at Rs. 35; so they are almost giving a subsidy of Rs. 4 per sq. yd.

Shri Vishram Prasad: The hon. Minister says that Government pays some subsidies to the low-income group. As I have explained, land actually costs Rs. 19.5 only. How can the Government say that it is being subsidised while such a huge profit is being made?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): The cost of land acquired may be Rs. 5 or Rs. 7. But all the land that is acquired is not sold for building purposes. Space has to be allotted for roads, parks, schools, etc. So, that cost has also to be distributed on the residential plots that are sold.

Shri Vishram Prasad: What is the total area acquired and what percentage of it is set apart for other purposes?

Shri Hathi: About forty per cent is used for building purposes. Development charges have also to be incurred.

श्री यशपाल सिंह : शुरू में यह जमीनें जिन किसानों से ली गई थीं तो यह उनसे ४–५ रुपये गज तक ली गई थीं तो क्या अब उनको भी इस प्राफ़िट में से कुछ हिस्सा मिलेगा ?

श्री ललितनारायण मिश्र : उनको तो हमने जमीनों की क़ीमत दे दी थी । उनको इस में से अब कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा ।

Shri Kapur Singh: Can the Government give this House an idea as to what would be the open market price of the plot which they have sold for Rs. 35 but which they have acquired for Rs. 5?

Shri L. N. Mishra: It is difficult to say but our information is that open market prices are varying between Rs. 50 and Rs. 150 per sq. yd.

Shri Kapur Singh: Then why is it that 150 worth land is taken away at the rate of Rs. 5 from the poor cultivator?

Shri L. N. Mishra: It is not taken by force; land was acquired long time back.

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जमीन किस हिसाब से बेची गई है और कितने ऐसे प्लाट हैं जिन पर कि अभी मकान नहीं बने हैं ?

श्री ललितनारायण मिश्र : यह मकान बनाने का सवाल नहीं है बल्कि यह तो एलौटमेंट ऑफ़ लैंड का सवाल है । जैसा मैंने बतलाया नवम्बर, १९६१ में करीब ७३ प्लाट्स सफदरजंग एरिया में और ५२५ प्लाट्स नजफगढ़ में लौट्स के हिसाब से लो इनकम ग्रुप वालों को दिये गये हैं ।

श्री काशी राम गुप्त : यह जमीन जिन लोगों को दी गई है वे सरकारी मुलाजिम हैं या अन्य वर्ग के लोग हैं और उनको कर्जा भी दिया जायेगा या नहीं ?

श्री ललितनारायण मिश्र : जिन व्यक्तियों की सालाना आमदनी ६००० रुपये से कम है वे लोग इसमें आये हैं ।

श्री काशी राम गुप्त : वे सरकारी नौकर हैं या और लोग हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बतला तो दिया कि जिन लोगों की सालाना आमदनी ६००० रुपये से कम है वे इस में आये हैं ।

श्री काशी राम गुप्त : जिन लोगों को प्लाट्स दिये गये हैं वे कौन हैं सरकारी नौकर हैं या और भी लोग हैं ?

श्री ललितनारायण मिश्र : उसमें दोनों ही तरह के लोग हैं । प्राइवेट आदमी भी हैं और सरकारी मुलाजिम भी हैं ।

श्री काशी राम गुप्त : उनको मकान बनाने के लिए क्या कर्जा भी दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो दूसरा सवाल हो गया ।

श्री काशी राम गुप्त: जो सरकारी नौकर हैं और जिनको जमीन मिल गयी है उन को तो कर्जा सरकार आम तौर से देती ही है लेकिन दूसरे लोगों को भी कर्जा दिया जायगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री रामसेवक यादव : यह जो ५ रुपये प्रति गज की दर से जमीन हासिल की गई है वह कितनी जमीन है और वह किन लोगों की जमीन है ? किसानों की है या अन्य लोगों की है ?

श्री ललितनारायण मिश्र : यह कहना मुश्किल है । जमीन पहले ले ली गई थी और दी अब गई है । यह जमीन उन व्यक्तियों को जो कि अपना मकान बनाना चाहते हैं और जिनकी कि आमदनी ६००० रुपया सालाना से कम है उनको यह जमीन दी जा रही है ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि जो जमीन ऐक्वायर की गई है यह किन की है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा तो कि यह बतलाना मुश्किल है । माननीय सदस्य जरा पूरा उनका उत्तर तो सुनें ।